THE HAWK
8-12-2019

R F Nariman and S prompt steps were taken." weeks from today". PTI given you strength but Dhruv Mehta, PTI

Side Event On Land Degradation Neutrality And REDD+ Readiness In India

• @ India Pavilion Of COP 25 Of UNFCCC At Madrid (Spain)

Dehradun: Indian Council of Forestry Research and Education in collaboration with International Centre for Integrated Mountain Development and GIZ hosted a side event on 'Land Degradation Neutrality and REDD+ Readiness in India' at India Pavilion of Twenty Fifth Session of Conference of Parties (COP 25) of United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) at Madrid (Spain). The event has apprised the global audience about Government of India's initiatives for land degradation neutrality, salient features of National REDD+ Strategy and various forestry programmes & projects for achieving climate change mitigation and land degradation neutrality in India by 2030. Side event was organised on 06 December 2019 at COP 25, MADRID

Dr. Suresh Gairola, Director General, ICFRE chaired the session of side event and highlighted that policies, laws and regulations related to forests in India are conservation centric and mainly focused on enhancement of forest and tree cover for sustainable flow of ecosystem goods and services for well-being of the communities. Various programmes and projects are being implemented in the country for sustainable management of forests as well as for meeting the Nationally Determined Contribution Goal, Sustainable Development Goal and Land Degradation Neutrality targets. India is one of the top ten countries where forest and tree cover are increasing and forests are net sink of carbon dioxide. He stated that Hon'ble Prime Minister while addressing a high-level segment meeting of the Conference of Parties (COP14) to United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) on 9 September 2019 announced to set up a Centre for Excellence in India at the Indian Council of Forestry Research and Education and to promote south-south cooperation with friendly countries who may wish to access knowledge, technologies and training of manpower to address the land degradation issues. Further, he highlighted the salient features of National REDD+ Strategy and contribution of ICFRE research in achieving climate change mitigation and land degradation neutrality targets.

Mr Rajendra Shende, Chairman, TERRE Policy Centre and former Director UNEP has highlighted the women led initiatives in climate change mitigation and climate education being conducted by TERRE Policy Centre in the Tribal District of Odisha. He also appreciates the research done by ICFRE for restoration of degraded forest lands and climate change mitigation, and civil society could provide assistance to ICFRE in capacity building of the stakeholders on sustainable land management through Centre for Excellence.

Mrs. Mechthild Caspers, Head of Division, Precautionary Soil Conservation, Peatland Conservation; Biological Diversity and Climate Change Division of Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety (BMU), Federal Republic of Germany stated that BMU is supporting the developing countries on forest restoration through International Climate Initiative. She appreciated the works done under REDD+ Himalaya Project implemented by ICIMOD and GIZ in partnership with REDD+ focal points in four Hindu Kush Himalayan countries Bhutan, India, Myanmar and Nepal which is mainly focusing on capacity building and knowledge dissemination through South-South cooperation.

Mr. A K Rastogi, Special Secretary, Department of Forest Environment and Climate Change, Govt of Jharkhand highlighted the contribution of communities of Jharkhand in climate change and carbon mitigation through sustainable management of forest and other natural resources.

Mr Thaung Naing Oo, Director, Forest Research Institute Myanmar shared the progress made by Myanmar with respect to REDD+ readiness and role of REDD+ in achieving NDC and SDG. Delegates from many countries participated in the side event including Union Minister Mr. Ohn Win, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation of Myanmar and express their desire to participate in the centre of excellence being established at ICFRE for addressing the issue related to land degradation neutrality. Dr. R.S. Rawat, Scientist Incharge, Biodiversity and Climate Change Division, ICFRE has coordinated the session of the side event. He acknowledged the supports provided by the ICIMOD and GIZ through REDD+ Himalaya Project, and Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India for organising the side event at COP 25.

AMAR UJALA

8-12-2019

देश में बढ़ रहा वनों का क्षेत्रफल

देहरादून। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और जीआईजेड के सहयोग से इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने लैंड डीग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एंड आरईडीडी प्लस रेडीनेस इन इंडिया पर एफआरआई में साइड इवेंट किया। जिसमें 2030 तक भारत में भूमि क्षरण तटस्थता, राष्ट्रीय आरईडीडी प्लस, रणनीति और विभिन्न वानिकी कार्यक्रमों आदि पर चर्चा हुई। महानिदेशक आईसीएफआरई डॉ. सुरेश गरोला ने साइड इवेंट के सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि भारत उन शीर्ष 10 देशों में से एक है, जहां वन और वृक्षों के क्षेत्र बढ़ रहे हैं। यूएनईपी के पूर्व निदेशक राजेंद्र, विशेष सचिव झारखंड सरकार एके रस्तोगी, वन अनुसंधान संस्थान म्यांमार के निदेशक थांग निंग ओओ, डॉ. आरएस रावत ने भी विचार रखे।

DAINIK JAGRAN
9-12-2019

भारत में बढ़ रहे वन क्षेत्र कार्बन सिंक में इजाफा

जागरण संवाददाता, देहरादून: आइसीएफआरई में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवपलमेंट और जीआइजेड के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में भारत में वन व वृक्षों के आवरण को बढ़ाने पर बल दिया गया। ताकि वर्ष 2030 तक के लक्ष्य के अनुरूप कार्बन डाईऑक्साइड का सिंक बढ़ाया जा सके। विशेषज्ञों ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि यहां कार्बन सिंक निरंतर बढ़ रहा है। आइसीएफआरई के महानिदेशक डॉ. एससी गैरोला ने कहा कि वनों के सतत् प्रबंधन और भूमि की हानि को रोकने के लिए तमाम स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नौ सितबंर 2019 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिक्केशन में भारत में इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा कर चुके हैं। इस मौके पर राजेंद्र शेंडे, मेचिल्ड कैस्पर्स, एके रस्तोगी आदि उपस्थित रहे।

GARH SAMVEDNA
8-12-2019

जलवायु परिवर्तन शमन और भूमि क्षरण तटस्थता को लेकर सरकार की योजनाओं से वैश्विक दर्शकों को अवगत कराया

देहरादून, गढ़ संवेदना न्यूज़ नेटवर्क। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और जीआईजेड के सहयोग से इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने भारत के लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एंड आरईडीडी रेडीनेस इन इंडिया पर एक साइड इवेंट की मेजबानी की। मैड्रिड (स्पेन) में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन इस कार्यक्रम ने 2030 तक भारत में भूमि क्षरण तटस्थता, राष्ट्रीय रणनीति और विभिन्न वानिकी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए जलवायु परिवर्तन शमन और भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं की भारत सरकार की पहल के बारे में वैश्विक दर्शकों को अवगत कराया है। डा. सुरेश गरोला महानिदेशक आईसीएफआरई ने साइड इवेंट के सत्र की अध्यक्षता की और इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में वनों से संबंधित नीतियां, कानून और नियम संरक्षण केंद्रित हैं और मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के सामान और सेवाओं के सतत प्रवाह के लिए वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। समुदायों की भलाई। देश में वनों के सतत प्रबंधन के लिए और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य और भूमि उन्नयन तटस्थता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

भारत उन शीर्ष दस देशों में से एक है जहां वन और वृक्षों के आवरण बढ़ रहे हैं और वन कार्बन डाइऑक्साइड के शुद्ध सिंक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन में पार्टियों की सम्मेलन की एक उच्च–स्तरीय खंड बैठक को संबोधित करते हुए भारत में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद और मैत्रीपूर्ण देशों के साथ दक्षिण–दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो भूमि क्षरण के मुद्दों का समाधान करने के लिए ज्ञान, प्रौद्योगिकियों और जनशक्ति के प्रशिक्षण तक पहुंचना चाहते हैं। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय ल्क् ध की रणनीति और जलवायु परिवर्तन शमन और भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनुसंधान के योगदान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। राजेंद्र शेंडे चेयरमैन टीईआरआई नीति केंद्र और पूर्व निदेशक यूएनईपी ने ओडिशा के आदिवासी जिले में टीईआरआई नीति केंद्र द्वारा संचालित की जा रही जलवायु परिवर्तन शमन और जलवायु शिक्षा में महिलाओं के नेतृत्व वाली पहल पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अपमानित वन भूमि और जलवायु परिवर्तन शमन की बहाली के लिए आईसीएफआरई द्वारा किए गए शोध की भी सराहना की और सिविल

सोसाइटी सेंटर फॉर एक्सीलेंस के माध्यम से स्थायी भूमि प्रबंधन पर हितधारकों की क्षमता निर्माण में आईसीएफआरई को सहायता प्रदान कर सकती है। उन्होंने चार हिंदू कुश हिमालयी देशों भूटान, भारत, म्यांमार और नेपाल में आरईडीडी फोकल पॉइंट के साथ भागीदारी में आईसीआईएमओडी और जीआईजेड द्वारा कार्यान्वित आरईडीडी हिमालय परियोजना के तहत किए गए कार्यों की सराहना की, जो मुख्य रूप से दक्षिण–दक्षिण सहयोग के माध्यम से क्षमता निर्माण और ज्ञान प्रसार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव एके रस्तोगी, झारखंड सरकार ने वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और कार्बन शमन में झारखंड के समुदायों के योगदान पर प्रकाश डाला। वन अनुसंधान संस्थान म्यांमार के निदेशक थांग निंग ओओ ने एनडीसी और एसडीजी प्राप्त करने के लिए म्यांमार द्वारा की गई प्रगति को आरईडीडी तत्परता और आरईडीडी प्लस की भूमिका के संबंध में साझा किया। डॉ. आर.एस. रावत, वैज्ञानिक प्रभारी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन प्रभाग, आईएफआरई ने साइड इवेंट के सत्र का समन्वय किया है। उन्होंने हिमालया प्रोजेक्ट के माध्यम से आईसीआईएमडी और जीआईजेड द्वारा प्रदान किए गए समर्थन, और सीओपी, 25 में साइड इवेंट के आयोजन के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, द्वारा स्वीकार किए जाते हैं।

SHAH TIMES
8-12-2019

भारत में लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी और रेड प्लस पर साइड इवेंट आयोजित

भारत में बढ़ रहे वन और वृक्षों के आवरण: डॉ. गैरोला

■ आईसीएफआरई महानिदेशक ने की सत्र की अध्यक्षता

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और गिज के सहयोग से इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने भारत के लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एंड रेड प्लस रेडीनेस इन इंडिया पर एक साइड ईवेंट की मेजबानी की। मैड्रिड (स्पेन) में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। इस कार्यक्रम ने 2030 तक भारत में भूमि क्षरण तटस्थता राष्ट्रीय रेड प्लस रणनीति और विभिन्न वानिकी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए जलवायु परिवर्तन शमन और भूमि क्षरण तटस्थता को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं की भारत सरकार की पहल के बारे में वैश्विक दर्शकों को अवगत कराया है।

डॉ. सुरेश गरोला, महानिदेशक आईसीएफआरई ने साइड इवेंट के सत्र की अध्यक्षता की और इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में वनों से संबंधित नीतियां, कानून और नियम संरक्षण केंद्रित हैं और मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के सामान और सेवाओं के सतत प्रवाह के लिए वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने पर केंद्रित हैं। समुदायों की भलाई। देश में वनों के सतत प्रबंधन के लिए और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य और भूमि उन्नयन तटस्थता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत उन शीर्ष दस देशों में से एक है जहां वन और वृक्षों के आवरण बढ़ रहे हैं और वन कार्बन डाइऑक्साइड के शुद्ध सिंक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विगत 9 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन में पार्टियों की सम्मेलन की एक उच्च-स्तरीय खंड बैठक को संबोधित करते हुए भारत में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद और मैत्रीपूर्ण देशों के साथ दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो भूमि क्षरण के मुद्दों का समाधान करने के लिए ज्ञान, प्रौद्योगिकियों और जनशक्ति के प्रशिक्षण तक पहुंचना चाहते हैं। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय रेड प्लस की रणनीति और जलवायु परिवर्तन शमन और भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्यों को प्राप्त करने में आईसीएफआरई अनुसंधान के योगदान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

राजेंद्र शेंडे, चेयरमैन टैरी नीति केंद्र और पूर्व निदेशक यूएनईपी ने ओडिशा के आदिवासी जिले में टैरी नीति केंद्र द्वारा संचालित की जा रही जलवायु परिवर्तन शमन और जलवायु शिक्षा में महिलाओं के नेतृत्व वाली पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने वन भूमि और जलवायु परिवर्तन शमन की बहाली के लिए आईसीएफआरई द्वारा किए गए शोध की भी सराहना की और सिविल सोसाइटी सेंटर फॉर एक्सीलेंस के माध्यम से स्थायी भूमि प्रबंधन पर हितधारकों की क्षमता निर्माण में आईसीएफआरई को सहायता प्रदान कर सकती है। कार्यक्रम में डॉ. आर.एस. रावत वैज्ञानिक प्रभारी जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन प्रभाग आईसीएफआरई ने साइड इवेंट के सत्र का समन्वय किया। साइड इवेंट में कई देशों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे।

THE HIMACHAL TIMES
8-12-2019

ICFRE holds Side Event on 'Land Degradation Neutrality, REDD+ Readiness in India'

DEHRADUN, DEC 7 (HTNS) The Indian Council of Forestry Research and Education in collaboration with International Centre for Integrated Mountain Development and GIZ hosted a side event on 'Land Degradation Neutrality and REDD+ Readiness in India' at India Pavilion of Twenty Fifth Session of Conference of Parties (COP 25) of United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) at Madrid (Spain). The event apprised the global audience about Government of India's initiatives for land degradation neutrality, salient features of National REDD+ Strategy and various forestry programmes and projects for achieving climate change mitigation and land degradation neutrality in India by 2030. The Side Event was organized on 6 December at COP 25, Madrid.

Dr Suresh Gairola, Director General, ICFRE chaired the session of Side Event and highlighted that the policies, laws and regulations related to forests in India are conservation centric and mainly focused on enhancement of forest and tree cover for sustainable flow of ecosystem goods and services for well-being of the communities. He stated that Prime Minister

Narendra Modi while addressing a high-level segment meeting of the Conference of Parties (COP14) to United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) on 9 September announced for setting up a Centre for Excellence in India at the Indian Council of Forestry Research and Education and to promote south-south cooperation with friendly countries. Further, he highlighted the salient features of National REDD+ Strategy and contribution of ICFRE research in achieving climate change mitigation and land degradation neutrality targets.

Rajendra Shende, Chairman, TERRE Policy Centre and former Director UNEP highlighted the women led initiatives in climate change mitigation and climate education being conducted by TERRE Policy Centre in the Tribal District of Orissa.

Mechthild Caspers, Head of Division, Precautionary Soil Conservation, Peatland Conservation; Biological Diversity and Climate Change Division of Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety (BMU), Federal Republic of Germany stated that BMU is supporting the developing countries on forest restoration through International Climate Initiative. She appreciated the works done under REDD+ Himalaya Project implemented by ICIMOD and GIZ in partnership with REDD+ focal points in four Hindu Kush Himalayan countries of Bhutan, India, Myanmar and Nepal. AK Rastogi, Special Secretary, Department of Forest Environment and Climate Change, Government of Jharkhand highlighted the contribution of communities of Jharkhand in climate change and Carbon mitigation through sustainable management of forest and other natural resources.

Delegates from many countries participated in the side event including Union Minister Ohn Win, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation of Myanmar.

Dr RS Rawat, Scientist Incharge, Biodiversity and Climate Change Division, ICFRE coordinated the session of the side event.

JAN BHARAT MAIL

8-12-2019

जलवायु परिवर्तन शमन और भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने की पहल के बारे में बताया

देहरादून, संवाददाता। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और जीआईजेड के सहयोग से इंडियन काउंसिल ऑफफॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने भारत के लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एंड आरईडीडी रेडीनेस इन इंडिया पर एक साइड इवेंट की मेजबानी की। मैड्रिड (स्पेन) में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन इस कार्य क्रम ने 2030 तक भारत में भूमि क्षरण तटस्थता, राष्ट्रीय लक्ष्य रणनीति और विभिन्न वानि की कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए जलवायु परिवर्तन शमन और भूमि क्षरण तट स्थता को प्राप्त करने के लिए परियोजनाओं की भारत सरकार की पहल के बारे में वैश्विक

दर्शकों को अवगत कराया है। डा. सुरेश गरोला महानिदेशक आईसीएफआरई ने साइड इवेंट के सत्र की अध्यक्षता की और इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत में वनों से संबंधित नीतियां, कानून और नियम केंद्रित हैं और मुख्य रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के सामान और सेवाओं के सतत प्रवाह के लिए वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।

समुदायों की भलाई। देश में वनों के सतत प्रबंधन के लिए और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य और भूमि उन्नयन तटस्थता लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और परियो जनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत उन शीर्ष दस देशों में से एक है जहां वन और वृक्षों के आवरण बढ़ रहे हैं और वन कार्बन डाइऑक्साइड के शुद्ध सिंक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 9 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन में पार्टियों की सम्मेलन की एक उच्च-स्तरीय खंड बैठक को संबोधित करते हुए भारत में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद और मैत्रीपूर्ण देशों के साथ दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो भूमि क्षरण के मुद्दों का समाधान करने के लिए ज्ञान, प्रौद्योगिकियों और जनशक्ति के प्रशिक्षण तक पहुंचना चाहते हैं। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय लक्ष्य की रणनीति और जलवायु परिव र्तन शमन और भूमि क्षरण तटस्थता लक्ष्यों को प्राप्त करने में अनुसंधान के योगदान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला।

THE PIONEER
9-12-2019

ICFRE holds event on COP 25 underway in Madrid

PNS ■ DEHRADUN

During the twenty fifth session of Conference of Parties (COP 25) of United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) underway at Madrid in Spain, the Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) in collaboration with International Centre for Integrated Mountain Development and GIZ hosted a side event on land degradation neutrality and REDD+ readiness in India.

The event apprised the global audience about Government of India's initiatives for land degradation neutrality, salient features of National REDD+ Strategy and various forestry programmes and projects for achieving climate change mitigation and land degradation neutrality in India by 2030. Chairing the event, the ICFRE director general Suresh Gairola highlighted that policies, laws and regulations related to forests in India are conservation centric and mainly focused on enhancement of forest and tree cover for sustainable flow of ecosystem goods and services for well-being of the communities.

Various programmes and projects are being implemented in the country for sustainable management of forests as well as for meeting the Nationally Determined Contribution Goal, Sustainable Development Goal and Land Degradation Neutrality targets.

India is one of the top ten countries where forest and tree cover are increasing and forests are net sink of carbon dioxide. He stated that Prime Minister Narendra Modi while addressing a high level segment meeting of the COP14 had

announced to set up a Centre for Excellence in India at the ICFRE and to promote south-south cooperation with friendly countries who may wish to access knowledge, technologies and training of manpower to address the land degradation issues. Further, he highlighted the salient features of National REDD+ Strategy and contribution of ICFRE research in achieving climate change mitigation and land degradation neutrality targets.

Chairperson of TERRE Policy Centre and former UNEP director Rajendra Shende highlighted the women led initiatives in climate change mitigation and climate education being conducted by TERRE Policy Centre in the tribal region of Odisha. He also appreciated the research done by ICFRE for restoration of degraded forest lands and climate change mitigation.

Delegates from various countries participated in the side event and expressed their desire to participate in the centre of excellence being established at ICFRE for addressing issue related to land degradation neutrality.

UTTAR BHARAT LIVE
9-12-2019

उतर भारत लाइब

देहरादून। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट और के सहयोग से इंडियन काउंसिलऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ने भारत के लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एंड रेडीनेस इन इंडिया पर एक साइड ईवेंट की मेजबानी की। मैड्रिड (स्पेन) में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र फ्रेंमवर्क कन्वेंशन।

Doon-based ICFRE hosts session on land degradation in Spain

SHIVANI AZAD, TNN ● DEHRADUN
1 DAY AGO

Dehradun: Doon-based Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) hosted a session on 'Land Degradation Neutrality and REDD+ Readiness in India' at India Pavilion of Twenty Fifth Session of Conference of Parties (COP 25) of United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Madrid, Spain on Friday.

Through the event, ICFRE apprised the global audience about India's initiatives for land degradation neutrality, salient features of National REDD+ Strategy, and various forestry programmes and projects for achieving climate change mitigation and land degradation neutrality in India by 2030.

Dr Suresh Gairola, director general, ICFRE, chaired the session of side event and highlighted that the policies, laws, and regulations related to forests in India are conservation-centric and mainly focused on enhancement of forest and tree cover for sustainable flow of ecosystem goods and services for well-being of the communities.

The session was hosted in collaboration with International Centre for Integrated Mountain Development and GIZ.

"Various programs and projects are being implemented in the country for sustainable management of forests as well as for meeting the Nationally Determined Contribution Goal, Sustainable Development Goal and Land Degradation Neutrality targets. India is one of the top ten countries where forest and tree cover are increasing and forests are net sink of carbon dioxide," said SC Gairola, DG-ICFRE, Dehradun.

Rajendra Shende, chairman, TERRE Policy Centre and former Director UNEP highlighted the women-led initiatives in climate change mitigation and climate education being conducted by TERRE Policy Centre in the tribal district of Odisha. He also appreciated the research done by ICFRE for restoration of degraded forest lands and climate change mitigation, and civil society could provide assistance to ICFRE in capacity building of the stakeholders on sustainable land management through Centre for Excellence.

TIMES OF INDIA
(News Portal)
8-12-2019